उत्तराखण्ड शासन, न्याय अनुभाग–2

संख्या-133-दो(8) / XXXVI(2) / 2011-119-दो(8) / 2011 देहरादून : दिनांक / 5 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश / कार्यालय ज्ञाप संख्या—498/ XXVII (1)/2007, दिनांक 05—06—2007 के प्रस्तर—3(3) में प्राविधानित है कि किसी परियोजना / कार्य को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व परीक्षणार्थ प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के स्तर पर संबंधित प्रमुख सचिव / सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया जायेगा।

2— उक्त शासनादेश में की गई उपरोक्त व्यवस्था के कम में, व्यय वित्त समिति को सन्दर्भित किये जाने से पूर्व परियोजनाओं / कार्यों के प्रस्तावों / आगणनों के विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतुं न्याय विभाग के अन्तर्गत निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :-

प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन
निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली,
जिला नैनीताल

3— अधिशासी अभियन्ता, कार्यदायी संस्था सदस्य

4- अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / पेयजल / सिंचाई, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अभियन्ता, जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से अन्यून हो सदस्य

इसके अतिरिक्त उक्तानुसार गठित समिति द्वारा योजना/परियोजना/अनावर्तक आदि मदों के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के प्रस्तर—3(3) के बिन्दु—(क) से (थ) का भी औचित्यपूर्ण परीक्षण किया जायेगा।

> (डी०पी० गैरोला) प्रमुख सचिव।

संख्याः / 6 3 / (1) / xxxvI(2) / 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- उक्तानुसार गठित समिति के नामित सदस्यगण।
- 7- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि न्याय
- विभाग के जीठओठ में इसे शामिल करें।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से. (धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी) संयुक्त सचिव।